भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 434
01 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: किसान क्रेडिट कार्ड ऋण

***434. श्री आनंद भदौरियाः**

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि कृषि क्षेत्र में फसलों का मूल्य और एमएसपी लाभकारी न होने के कारण, किसान क्रेडिट कार्ड की शुरूआत होने से विगत चार वर्षों में अशोध्य ऋणों में 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को संकट की स्थिति से उबारने के लिए एमएसपी के संबंध में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 01 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ किसान क्रेडिट कार्ड ऋण के संबंध में श्री आनंद भदौरिया द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 434 के भाग (क) से (ङ) का उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न बैंकिंग क्षेत्रों में किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) खातों में नॉन परफॉर्मिंग ऐसेट्स (एन.पी.ए.) के हिस्सेदारी में लगातार गिरावट आई है, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में विस्तार से बताया गया है:

एनपीए की स्थिति (%) – केसीसी योजना				
बैंक ग्रुप	**केसीसी - एनपीए (%)**			
	31 मार्च ,2022	**31 मार्च ,2023**	**31 मार्च ,2024**	**31 दिसंबर ,2024**
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों	15.1	14.9	14.0	14.16
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों	9.5	7.8	7.1	*लागू नहीं**
सहकारी बैंकों	6.9	6.8	6.5	*लागू नहीं**

*उपलब्ध नहीं डेटा सोर्स: आरबीआई और नाबार्ड

हालांकि पिछले कुछ वर्षों में केसीसी खातों में एनपीए की कुल राशि में वृद्धि देखी गई है, लेकिन इन वर्षों में केसीसी खातों के तहत दिए गए कुल कृषि ऋण में भी वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान, केसीसी खातों में दिया गया ऋण 31 मार्च 2022 तक 9.38 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 31 दिसंबर 2024 तक 10.05 लाख करोड़ रुपये हो गया।

(ग) और (घ): प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में वर्ष 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग (एनसीएफ) का गठन किया गया था । स्वामीनाथन आयोग द्वारा प्रस्तुत 'किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति के मसौदे' के आधार पर, जिसमें आयोग की प्रमुख सिफारिशें शामिल थीं, सरकार ने 'किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति 2007' (एनपीएफ 2007) को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य खेती की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार करना और किसानों की शुद्ध आय में वृद्धि करना था। इन सिफारिशों के संबंध में वर्ष 2007 में एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया , जिसने सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले 201 कार्य बिंदुओं की सिफारिश की। सभी 201 कार्य बिंदुओं को कार्यान्वित किया जा चुका है ।

राष्ट्रीय किसान आयोग (एनसीएफ) ने भी सिफारिश की है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) उत्पादन की भारित औसत लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक होना चाहिए। इस सिफारिश को प्रभावी बनाने के लिए, सरकार ने 2018-19 के अपने केंद्रीय बजट में पूर्व निर्धारित सिद्धांत के रूप में एमएसपी को उत्पादन की लागत के न्यूनतम डेढ़ गुना के स्तर पर रखने की घोषणा की थी। तदनुसार, सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी को उत्पादन की भारित औसत लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक मार्जिन के साथ तय किया गया है ।

(ङ): प्रश्न नहीं उठता।

*****